कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

समरसता सम्मलेन, हरिद्वार 6

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का तमिलनाडु प्रवास 8

5 राज्यों में नए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति 9

सरकार की उपलब्धियां

'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' का शुभारंभ 10

प्रस्तुत हुई 'सागरमाला' राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना 11

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया 12

वैचारिकी

भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप

अटल बिहारी वाजपेयी 13

श्रद्धांजलि

डॉ. भीमराव अम्बेडकर : एक दूरद्रष्टा विद्वान 14

लेख

वैश्विक समुद्री क्षेत्र में पुनर्जीवित हो भारत की प्रतिष्ठा

– **नरेंद्र मोदी** 22

सुकन्या समृद्धि खाता : बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की प्रतिबद्धता

– **आमिर अमीन नौशहरी** 26

अन्य

कृष्णानगर (पश्चिम बंगाल) रैली 15

प्रधानमंत्री का कटरा (जम्मू-कश्मीर) दौरा 17

भारत-मालदीव संबंध 18

महामंत्री प्रतिवेदन 28

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को **अक्षय तृतीया** की हार्दिक शुभकामनाएं!

फेसबुक

सोशल मीडिया से...

twitter

श्री नरेन्द्र मोदी

सरकार की हर नीति- ग्रामीण विद्युतीकरण, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा से आवास- गांवों के विकास के आसपास केंद्रित है। डिजिटल कनेक्टिविटी हो या किसानों की दोगुनी आय, हमारी पहल का दायरा बहुत बड़ा है और हम वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हैं।

श्री अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दृढ़ निश्चय के साथ बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में हम भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, दलित और शोषित वर्गों के कल्याण एवं उनके जीवन-स्तर में उत्थान लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री रविशंकर प्रसाद

भारत में 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं... 40 करोड़ इंटरनेट के यूजर्स हैं।

श्री प्रकाश जावडेकर

ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का लक्ष्य समस्त गांवों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करके सामाजिक सद्भाव, ग्रामीण विकास, किसानों की प्रगति और गरीब लोगों की जीविका के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयास करना है।

श्री राजीव प्रताप रूडी

शिक्षा से समृद्धि, कौशल से अभिवृद्धि।

पाथेय

हर एक कार्यकर्ता को अपने आपको पूछना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं वह स्वार्थ, ईर्ष्या, राग द्वेष से प्रेरित तो नहीं? और इस मामले में कार्यकर्ता को हमेशा आत्मनिरीक्षण करने की आदत चाहिए। सबको साथ लेने की दृष्टि से कार्यकर्ताओं को और लोगों के बारे में सामंजस्य और उदारता का भाव रखना चाहिए। अपने प्रति कठोरता रखकर ही दृढ़ संकल्पी कार्यकर्ता कुछ कर सकते हैं। देश में राजनीति की दिशा भी बदल सकते हैं। क्या यह सारी जवाबदारी लेने के लिए हम सिद्ध है?

भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे हुए देश में सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी होना जरूरी है, इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में समर्पित और क्रियाशील कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है।

- कुशाभाऊ ठाकरे

ग्राम उदय से भारत उदय

इस वर्ष 14 अप्रैल को देश ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने हरिद्वार में एक जनसभा को संबोधित कर बाबा साहेब के योगदान को याद किया। पूरे देश में बाबा साहेब की जयंती एक समरस समाज के निर्माण के संकल्प के साथ मनाया गया। बाबा साहेब को संविधान निर्माता, सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा एवं दलित विचारक के रूप में जाना जाता है। एक बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी होने के साथ-साथ बाबा साहेब ने राष्ट्रीय जीवन को अपने विचारों से समृद्ध किया है। वे एक दूरद्रष्टा एवं विचारक थे जो जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता तथा विभिन्न सामाजिक बुराइयों से लड़ते रहे। उनके विचार निरंतर पूरे राष्ट्र को प्रेरित कर दिशा दिखा रहे हैं।

बाबा साहेब की जयंती पर 'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' की शुरुआत उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अभियान का समापन 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन होगा। इस अभियान का लक्ष्य राज्य सरकारों तथा पंचायतों के माध्यम से बड़े स्तर पर सामाजिक समरसता, ग्रामीण विकास एवं किसानों के कल्याण के लिए प्रयास करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जमशेदपुर से सभी पंचायतों को संबोधन के साथ इस अभियान का समापन होगा। जमीनी स्तर पर पंचायतों के माध्यम से सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए यह एक बड़ा कदम है। जिससे गांवों के स्तर पर जीवन स्तर पर काफी सुधार होगा। लोगों में जागरूकता लाकर योजना एवं कार्यान्वयन के स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर 'सबका साथ, सबका विकास' के सपने को साकार किया जा सकता है। जिस प्रकार से अभियान की रचना की गई है लोग इसके प्रति आकर्षित होंगे तथा व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गांव, गरीब एवं किसान को अपने कार्यक्रमों एवं नीतियों में मजबूती देकर समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। इससे पूर्व किसी भी सरकार ने गांव, गरीब एवं किसान के विकास के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रावधान बजट में कहीं किया था। यह पहली बार है कि ग्रामीण विकास अब सरकार की प्राथमिकता में है तथा पंचायतों के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने एवं हर किसान को कृषि ऋण एवं तकनीक उपलब्ध कराने के लिए अनेक अभिनव योजनाएं कार्य कर रही है। साथ ही गरीबों के लिए अनेक बीमा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के वृहद योजनाएं लागू की गई है। इसी प्रकार से वित्तीय समावेषण के क्षेत्र में जन-धन योजना की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान इन योजनाओं से मिली बढ़त को सुदृढ़ कर भविष्य के लिये जमीन तैयार करेगी। इन सभी योजनाओं से बाबा साहेब के सपने साकार होंगे, जो निरंतर वंचितों एवं दलितों के लिए संघर्ष करते रहे। बाबा साहेब ने कहा था कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से राजनैतिक समानता तो मिल सकती है, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक समता लाए बिना विसंगतियों से नहीं उबरा जा सकता। अंत्योदय के सिद्धांत का अनुसरण कर सरकार निरंतर सामाजिक एवं आर्थिक समता की ओर कदम बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील एवं दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व में भाजपानीत एनडीए सरकार सामाजिक समरसता एवं विकास का मार्ग तीव्रता से प्रशस्त कर रही है। ■

भाजपा 'बाबा साहब' के सपनों को साकार करने में जुटी : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 14 अप्रैल को हरिद्वार, उत्तराखंड में भारत रत्न बाबा साहब भीवराव अंबेडकर की 125वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित समरसता सम्मलेन को सम्बोधित किया और लोगों से बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर भारत के नवनिर्माण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दृढ़ निश्चय के साथ बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें सभी जाति, समुदाय, वर्ग, भाषा, प्रांत इत्यादि के लिए समान अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके ताकि देश एकता और अखंडता के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए विश्व का नेतृत्त्व कर सके। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। श्री शाह ने कहा कि बाबा साहब ने देश के दलित, शोषित और उत्पीड़ित वर्ग के कल्याण एवं उनके जीवन-उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष किया, उनमें जागृति की अलख जगाई और वे समाज में भी समरसता का भाव लाने में काफी हद तक सफल रहे। श्री शाह ने कहा कि उनकी लड़ाई सामाजिक समरसता और बराबरी के लिए थी। उन्होंने कहा कि अपमान झेलने के बाद भी संविधान बनाते वक्त बाबा साहब ने किसी के प्रति बदले का भाव नहीं रखा, यह उनकी महानता को दर्शाता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आजकल बहुत सारी पार्टियां केवल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति और राजनीतिक लाभ के लिए बाबा साहब भीवराव अंबेडकर के नाम की राजनीति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ठीक इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना समय से ही बाबा साहब के सपनों को साकार करने की दिशा में गंभीर प्रयास करती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का मूल उद्देश्य ही 'अंत्योदय' है जो बाबा साहब के सिद्धांतों के ही अनुरूप है और हम विकास एवं सामाजिक न्याय को देश के हर गाँव, हर गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित और वंचितों तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित हैं।

भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े स्थानों के पुनरुद्धार का जिक्र करते हुए कहा कि यह भाजपा है, जिसने बाबा साहब की जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, बिरसा भूमि, परिनिर्वाण भूमि और समाधि भूमि को राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में स्थापित करने का काम किया है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उनके विचारों का दमन करने की कोशिश की, संविधान सभा से भी उन्हें बाहर रखने की कोशिश की और उनसे जुड़े स्थानों को भी समाज की मुख्य धारा से तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का काम भी

भाजपा की मोदी सरकार ने किया। श्री शाह ने कहा कि मैं इसके लिए कांग्रेस को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने न तो बाबा साहब से जुड़े स्थानों के संरक्षण का काम किया, न ही उनके विचारों के अनुरूप सरकार चलाई और न ही देश के दलितों, आदिवासियों, शोषितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए ही कुछ किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें इन कार्यों को पूरा करने का अवसर मिल रहा है।

श्री शाह ने कहा कि भाजपा मानती है कि यदि हमें भारत उदय करना है, देश के जन-जन तक सभी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना है, राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का सपना देखना है तो सबसे पहले गांवों का विकास जरूरी है और इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की मोदी सरकार ने इस वर्ष के बजट में कई सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात किया है, जिससे ग्राम विकास को बल मिला है।

गाँव के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता हर गांव और हर करस्बे का विकास है। उन्होंने कहा कि हमने प्रत्येक गांव के विकास के लिए लगभग 80 लाख और प्रत्येक करस्बे के विकास के लिए लगभग 21 करोड़ से एक अलग कोष का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि आजादी के 67 सालों बाद भी देश के 18,000 गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची थी।

उन्होंने कहा कि गांव के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता हर गांव और हर कस्बे का विकास है। उन्होंने कहा कि हमने प्रत्येक गांव के विकास के लिए लगभग 80 लाख और प्रत्येक कस्बे के विकास के लिए लगभग 21 करोड़ से एक अलग कोष का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि आजादी के 67 सालों बाद भी देश के 18,000 गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची थी।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने मात्र 1000 दिनों में देश में बिजली से वंचित हर गांव तक बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया है, एक वर्ष के अंदर ही लगभग एक तिहाई से अधिक गाँवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है।

श्री शाह ने कहा कि इसी तरह देश से बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने मुद्रा बैंक योजना, स्किल्ड इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रमों की शुरुआत की है, क्योंकि हमारा मानना है कि बेरोजगार को हम जब तक रोजगार नहीं दे देते, हम विकास के रास्ते पर नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि हम अपने युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देनेवाला बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा बैंक योजना के तहत देशभर के करोड़ों युवाओं को बिना किसी गारंटी के नगण्य दरों पर आसान ऋण उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि हमने बैंकों से कहा कि प्रत्येक ब्रांच से कम-से-कम 10 दलित और आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए। श्री शाह ने कहा कि इसी तरह, देश के किसानों के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इ-कृषि मंडी और स्वाइल हेल्थ कार्ड जैसे अभिनव योजनाओं का सूत्रपात किया ताकि किसान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुद को अकेला न महसूस करे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने लोगों को बाबा साहब की जन्म जयंती की बधाई देते हुए कहा, 'बाबा साहब के 125वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर केंद्र सरकार और पार्टी ने मिलकर देश में सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए 'ग्राम उदय से भारत उदय' आंदोलन की शुरुआत की है, 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि आप हर गांव, हर गली और हर घर तक मोदी सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित और आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाएं।' उन्होंने कहा कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए उनके सपने को साकार करना है और और मुझे विश्वास है कि हम गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के कल्याण और उनके जीवन-स्तर में व्यापक बदलाव लाने में सफल होंगे।■

भ्रष्टाचार में तीनों लिप्त–डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 13 अप्रैल को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में प्रेस वार्ता की और राज्य की बदहाली के लिए डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने राज्य की जनता से तमिलनाडु के विकास के लिए राज्य में भाजपा की अगुआई वाली एनडीए सरकार बनाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि डीएमके और उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही कांग्रेस तथा एआईएडीएमके–तीनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं चाहे वह आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, या टूजी का केस हो, चाहे वह एयरसेल–मैक्सिस डील विवाद हो या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पी. चिदंबरम के पुत्र के ऊपर ईडी का केस हो। उन्होंने कहा कि जब–जब ये पार्टियां सत्ता में आई हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम किया है और ये सभी मामले इनके भ्रष्टाचार के ही परिणाम हैं। श्री शाह ने कहा कि इसी भ्रष्टाचार के कारण एक मजबूत विकास की संभावनाओं वाला प्रदेश आज विकास के दौर में काफी पीछे है।

उन्होंने कहा कि डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस कभी भी तमिलनाडु में विकास का शासन नहीं दे सकती, यह केवल भारतीय जनता पार्टी की अगुआई वाली एनडीए गठबंधन की सरकार ही दे सकती है क्योंकि भाजपा केवल विकास की राजनीति में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार के भी 2 वर्ष होने को आये लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप हम पर नहीं लगा सका।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्त्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 2 सालों में विकास के लिए कई लोक–कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं लेकिन तमिलनाडु में इन योजनाओं को लागू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 'उदय' योजना का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की उदासीनता के कारण यह योजना अभी तक राज्य में शुरू ही नहीं हो पाई है, इसी तरह राज्य सरकार की जिद के कारण एम्स के लिए जगह का भी आवंटन अभी तक नहीं हो पाया है।

उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देश के गरीब युवाओं के स्वरोजगार के लिए चलाई जा रही मुद्रा बीमा योजना, देश की आम जनता की सामाजिक सुरक्षा के लिए लागू की गई बीमा योजनाएं आदि कई योजनाओं से जितना फायदा तमिलनाडु को मिलना चाहिए था, उतना फायदा राज्य सरकार के असहयोग के कारण राज्य की जनता अब तक नहीं उठा पाई है।

श्री शाह ने मोदी सरकार द्वारा तमिल मछुआरों की भलाई के लिए किये जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने श्रीलंका में पकड़े गए मछुआरों (जिन्हें वहां की सरकार ने फांसी की सजा तक दे दी थी) को न केवल छुड़ाया, बल्कि उनकी सकुशल वापसी भी सुनिश्चित की।

तमिल मछुआरों से सम्बंधित एक प्रश्न का जवाब देते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में हमारे आने के बाद से श्रीलंका से तमिल मछुआरों की रिहाई में काफी तेजी आई है, साथ ही मछुआरों

को किसी प्रकार की गोलीबारी का कोई सामना भी करना नहीं पड़ रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने जाफना में तमिल शरणार्थियों के कैम्प में जाकर उनसे बातचीत की और उनकी हौसला-अफजाई की। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा तमिल मछुआरों की समस्या के पूर्ण समाधान के लिए कटिबद्ध है।

भाजपा अध्यक्ष ने राज्य को दी गई केंद्रीय सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि कुदरती आपदा के समय केंद्र सरकार ने यह देखे बगैर कि राज्य में किसकी सरकार है, तमिलनाडु को हजारों करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई, ताकि राज्य के लोग संकट की घड़ी में भी अपने आपको अकेला न महसूस करें। श्री शाह ने कहा कि डीएमके-कांग्रेस और एआईएडीएमके - दोनों के शासन में रेत और शराब माफियाओं द्वारा राज्य की जनता का काफी शोषण किया गया है।

तमिलनाडु की अन्य राज्यों के साथ चल रहे जल विवाद पर पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए श्री शाह ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमने जल विवाद के स्थायी समाधान के लिए काफी गम्भीर प्रयास किया था, लेकिन पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस की केंद्र अथवा राज्य सरकारों ने इस मुद्दे के समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सभी राज्यों की सहमति से जल विवाद का पूर्णकालिक हल तलाशने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार गाँव, गरीब, किसान, युवा और मजदूरों के कल्याण के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु में भ्रष्टाचार और भयमुक्त विकास वाला शासन देने का वादा करते हैं।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले लोक सभा चुनाव में हमें लगभग 20 प्रतिशत मत मिले थे, उसी तरह, मुझे पूर्ण भरोसा है कि तमिलनाडु की जनता भाजपा को इस बार राज्य में शासन का एक मौका जरूर देगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि तमिलनाडु की भ्रष्टतम सरकारों में से एक इस सरकार को बदलिए, राज्य में भाजपा-गठबंधन की सरकार बनाइये और तमिलनाडु को विकास के पथ पर अग्रसर कीजिये। ■

5 राज्यों में नए भाजपा प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 8 अप्रैल को निम्नलिखित प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है।

कर्नाटक

श्री बी.एस. येदियुरप्पा

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री।

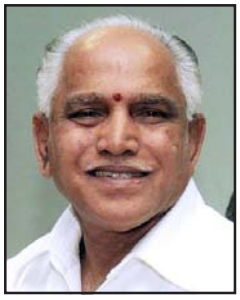

उत्तर प्रदेश

श्री केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश में फूलपुर सीट से सांसद। उत्तर प्रदेश में विधायक भी रह चुके हैं।

पंजाब

श्री विजय सांपला

केंद्रीय राज्य मंत्री और पंजाब के होशियारपुर से सांसद।

तेलंगाना

डॉ. श्री के. लक्ष्मण

मुर्शिदाबाद से विधायक हैं।

अरूणाचल प्रदेश

श्री तापिर गांव

पूर्व सांसद एवं महामंत्री, भाजपा।

सरकार की उपलब्धियां

'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' का शुभारंभ

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश स्थित 'महू' में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में 14 अप्रैल को 'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वह इस शुभ दिवस पर महू में हैं। उन्होंने इस अवसर पर यह स्मरण किया कि डॉ. अम्बेडकर ने समाज में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने समानता और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी थी।

श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने मान-सम्मान, मर्यादाओं के लिए नहीं लेकिन समाज की बुराईयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो। उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित हो करके भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल, 2016 तक चलने वाले ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' के तहत गांवों में होने वाले विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल का केंद्रीय बजट किसानों और गांवों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि विकास की पहलों को ग्रामीण विकास पर केंद्रित होना चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की जो भावना हमें दी, ये सब अभी भी पूरा होना बाकी है। आजादी के इतने सालों के बाद जिस प्रकार से हमारे गांव के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए था, जो बदलाव आना चाहिए था। बदले हुए युग के साथ ग्रामीण जीवन को भी आगे ले जाने का आवश्यक था। लेकिन ये दुख की बात है अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत का आर्थिक विकास 5-50 बढ़े

शहरों से होने वाला नहीं है। भारत का विकास 5-50 बढ़े उद्योगकारों से नहीं होने वाला। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है और लंबे समय तक स्थायी विकास करना है, तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा। तब जाकर के उस पर विकास की इमारत को हम स्थायी बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मैंने अफसरों को पूछा कि आजादी के अब 70 साल होने वाले है कुछ ही समय के बाद। कितने गांव ऐसे है जहां आजादी के 70 साल होने आए, अभी भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है, बिजली का तार नहीं पहुंचा है। आज भी वो गांव के लोग 18वीं शताब्दी की जिंदगी में जी रहे है, ऐसे कितने गांव है। मैं सोच रहा था 200-500 शायद, दूर-सुदूर कहीं ऐसी जगह पर होंगे जहां संभव नहीं होगा।

केंद्र सरकार द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण विकास पहलों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1000 दिनों की समय सीमा के भीतर उन 18000 गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, जो बिजली की सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि 'गर्व' एप के जरिये लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति में हो रही प्रगति का अवलोकन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में डिजिटल कनेक्टिविटी आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य का उल्लेख किया और कहा कि ग्रामीणों की क्रय क्षमता को निश्चित तौर पर बढ़ाना है, क्योंकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज से जुड़े संस्थानों को और ज्यादा मजबूत एवं और ज्यादा जीवंत बनाया जाना चाहिए। ■

सरकार की उपलब्धियां

प्रस्तुत हुई 'सागरमाला' राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को मुंबई में 'मेरीटाइम इंडिया समिट' के शुभारंभ के अवसर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना जारी की, जिसमें 'सागरमाला' की रूपरेखा का ब्यौरा दिया गया है। सागरमाला सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश में बंदरगाहों की अगुवाई में विकास की गति तेज करना है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के अहम हितधारकों और शिपिंग, बंदरगाह, जहाज निर्माण, विद्युत, सीमेंट एवं इस्पात क्षेत्रों की सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ व्यापक सलाह-मशविरा करने के बाद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है। यह न्यूनतम निवेश के साथ निर्यात-आयात एवं घरेलू व्यापार की लागत काफी हद तक कम करने संबंधी सागरमाला के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।

केंद्रीय शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि जल परिवहन को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स लागत में खासी कमी करने में मदद मिलेगी, जो चीन एवं यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में बहुत ज्यादा है।

रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि इस कार्यक्रम से लॉजिस्टिक्स लागत में तकरीबन 35,000 करोड़ रुपये की सालाना बचत संभव हो सकती है और इसके साथ ही वर्ष 2025 तक भारत के व्यापारिक निर्यात के बढ़कर 110 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। यही नहीं, लगभग 1 करोड़ नये रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जिनमें से 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार होंगे।

यह योजना इन चार रणनीतिक पहलुओं पर आधारित है- घरेलू कार्गो की लागत घटाने के लिए मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट का अनुकूलन करना, निर्यात-आयात कार्गो लॉजिस्टिक्स में लगने वाले समय एवं लागत को न्यूनतम करना, उद्योगों को लागत के और करीब स्थापित कर लागत को घटाना और बंदरगाहों के पास पृथक विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना कर निर्यात के मामले में प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर करना।

सागरमाला का लक्ष्य चार व्यापक क्षेत्रों में 150 से भी ज्यादा परियोजनाओं और पहलों के जरिये आवश्यक सकारात्मक असर सुनिश्चित करना है। इस मामले में विशेष ध्यान वाला दूसरा क्षेत्र बंदरगाहों की कनेक्टिविटी है, जिसके लिए 80 से भी ज्यादा परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

परियोजनाओं के तीसरे समूह का उद्देश्य बंदरगाहों की अगुवाई में औद्योगीकरण की संभावना का दोहन करना है, ताकि तटीय रेखा के साथ-साथ औद्योगिक एवं निर्यात विकास को नई गति प्रदान की जा सके। तटीय रेखा के पास अवस्थित 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) के जरिये इस उद्देश्य की पूर्ति की जाएगी।

आखिर में, कौशल विकास पर फोकस करते हुए तटीय समुदायों की संभावनाओं का दोहन किया जाएगा, ताकि बंदरगाहों की अगुवाई में औद्योगीकरण में सहूलियत हो सके। इसके अंतर्गत उठाए जाने वाले कदमों के तहत मछुआरों एवं अन्य तटीय समुदायों के लिए भी अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा भारत की तटीय रेखा के आसपास कई द्वीपों का विकास किया जाएगा। ■

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया

8 राज्यों की 21 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 'ई-नाम' की प्रायोगिक परियोजना (पायलट) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल से पारदर्शिता आएगी, जिससे किसान काफी हद तक लाभान्वित होंगे।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह कृषि समुदाय के लिए एक बड़ा बदलाव है एवं कृषि क्षेत्र को समग्र रूप में देखना होगा और इसके बाद ही किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार और तेजी से काम कर रही है और राष्ट्रीय कृषि बाजार उसी दिशा में उठाया एक महत्वपूर्ण कदम है।

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने किसानों की समस्या समझते हुए इस परियोजना पर तेजी से काम किया और आज 8 राज्यों की 21 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि सितंबर, 2016 तक इसमें 200 मंडियां शामिल हो जाएंगी और मार्च, 2018 तक 585 मंडियों को जोड़ दिया जाएगा।

केन्द्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर ने अपना जीवन गरीबों, अत्यंत पिछड़े वर्गों और किसानों को समर्पित कर दिया था, यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार को बाबा साहेब की 125वीं जयंती पर किसानों के लिए खोलने का फैसला किया। कृषि मंत्री ने इस परियोजना में मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने इस मौके पर बताया कि यह परियोजना एक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा संचालित होगी जिसे राज्य की मंडियों से जोड़ा जा रहा है। इसका सॉटवेयर सभी इच्छुक राज्यों को नि:शुल्क दिया गया है और कामकाज में मदद के लिए हर भागीदार मंडी में एक वर्ष के लिए एक जानकार व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत भारत सरकार, राज्यों की प्रस्तावित कृषि मंडी को 30 लाख रुपये का अनुदान दे रही है। इस पोर्टल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किसानों को 24 घंटे किसान हेल्पलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मंत्री महोदय ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने अपने लिए एक कृषि विकास वृक्ष की अवधारणा अपनाई है और इसी कृषि वृक्ष के अंदर कृषि मंत्रालय ने किसानों के समग्र विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं।

उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार हर दिशा में योजनाएं चला रही है। आखिर में कृषि मंत्री ने कहा कि भारत में पहली बार 'एक राष्ट्र-एक बाजार' विकसित हो रहा है और यह कृषि बाजार अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा, इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा।

इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अलावा, केन्द्रीय संचार एवं सूचना तकनीक मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री मोहन भाई कुंडरिया, डॉ. संजीव बालियान और कृषि सचिव श्री शोभन पट्टनायक मौजूद थे। ■

भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप

अटल बिहारी वाजपेयी

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र की स्पष्ट कल्पना लेकर चलें। राष्ट्र कुछ संप्रदायों अथवा जनसमूहों का समुच्चय मात्र नहीं, अपितु एक जीवमान इकाई है, जिसे जोड़-तोड़कर नही बनाया जा सकता। इसका अपना व्यक्तित्व होता है, जो उसकी प्रकृति के आधार पर कालक्रम का परिणाम है। उसके घटकों में राष्ट्रीयता की यह अनुभूति, मातृभूमि के प्रति भक्ति, उसके जन के प्रति आत्मीयता और उसकी संस्कृति के प्रति गौरव के भाव में प्रकट होती है। इसी आधार पर अपने-पराये का, शत्रु-मित्र, अच्छे-बुरे और योग्य-अयोग्य का निर्णय होता है।

जीवन की इन निष्ठाओं तथा मूल्यों के चारों ओर विकसित इतिहास, राष्ट्रीयत्व की भावना घनीभूत करता हुआ उसे बल प्रदान करता है। उसी से व्यक्ति से त्याग और समर्पण की, पराक्रम और पुरुषार्थ की, सेवा और बलिदान की प्रेरणा मिलती है।

भारत एक प्राचीन राष्ट्र

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। स्वतंत्रता की प्राप्ति से, इसके चिरकालीन इतिहास में एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ। किसी नवीन राष्ट्र का जन्म नहीं। नया राष्ट्र बनाने की चर्चा का परिणाम जीवन-मूल्यों की अवहेलना और आत्म-विस्मृति में हुआ है। फलत: हमारे राष्ट्रीय मानस में एक गांठ पड़ गई है और द्वैत भाव की सृष्टि हुई है। घर और बाहर के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के अलग-अलग आदर्श बन गए हैं। भारत के ऋषियों-महर्षियों, स्मृतिकारों, पुराण-निर्माताओं, साधु-संन्यासियों, कवि-कलाकारों, सम्राटों-सेनापतियों और संतों तथा सुधारकों ने जिस एकात्मक जीवन के ताने-बाने को बुना था, आज वह उपेक्षा तथा उपहास का विषय बनाया जा रहा है। जिन उपादानों ने हमें हजारों साल तक एक बनाये रखा, जिनके कारण हम बाहरी आक्रमण और आंतरिक विघटन के बावजूद अपने अस्तित्व को कायम रख सके, उन्हें आज तिरस्कृत किया जा रहा है। यह एकता की प्राप्ति का नहीं, बची-खुची एकता को भी खतरे में डालने का मार्ग है। आवश्यकता है कि हम अपने राष्ट्र की प्राचीनता को मान्य करें और उसके सही स्वरूप को समझें।

भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक एकता की अनुभूति ही राजनीतिक एकता के पक्ष की प्रेरक शक्ति रही है। राजनीतिक एकता के अभाव ने देश की सांस्कृतिक धारा को कभी खण्डित नहीं होने दिया। जहां एक ओर हम भारत की संस्कृति से अभिन्न रूप से सम्बद्ध अनेक राजनीतिक इकाइयों के प्रति उदासीन तथा सहिष्णु रहे हैं, वहां दूसरी ओर भारतीय संस्कृति से भिन्न उसके विकृत अथवा विरोधी भाव पर आधारित, कोई भी राजनीतिक सत्ता हमें मान्य नहीं हुई। हम सदैव उसके विरूद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। हमने एकरूपता की नहीं, अपितु एकता की कामना की है। फलत: देश में अनेक उपासना पद्धतियों, पंथों, दर्शनों, जीवन-प्रणालियों, भाषाओं, साहित्यों और कलाओं का विकास हुआ, जो सम्पन्नता की द्योतक हैं। हमें उनके प्रति अपनत्व और गौरव का भाव लेकर चलना होगा। किन्तु विविधता के नाम पर विभाजन को प्रोत्साहन देना भूल होगी। भारतीय संस्कृति कभी किसी एक उपासना पद्धति से बंधी नहीं रही और न उसका आधार प्रादेशिक ही रहा है। मजहब अथवा क्षेत्र के आधार पर पृथक् संस्कृति की चर्चा तर्क-विरुद्ध ही नहीं, भयावह भी है, क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता की जड़ पर ही कुठाराघात करती है।

क्षेत्र, प्रदेश, जाति, पंथ, भाषा, भूषा आदि के आधार पर भारतीय जन की पृथकता की कल्पना भ्रामक है। उनके आधार पर भारत में अनेक राष्ट्रों अथवा राष्ट्रीयताओं के अस्तित्व का विचार भी मूलत: अशुद्ध है। हम एक राज्य में रहने के कारण एक नहीं हैं, अपितु हम एक हैं, इसलिए भारत एक राष्ट्र है।

राष्ट्र के प्रति अनन्य निष्ठा ही राष्ट्रीयता का निकष होने के कारण भारत के सभी जनों को अपनी निष्ठाओं को इसके अधीन बनाना होगा। इसके लिए दोहरा प्रयत्न आवश्यक है। एक ओर जहां अपने प्रदेश, पंथ अथवा जाति के प्रति निष्ठा रखने वालों को राष्ट्रनिष्ठ बनाना होगा, वहां दूसरी ओर भारत से बाहर निष्ठा रखने वालों को फिर से, चाहे वे पाकिस्तान परस्त हों, अथवा रूस और चीन के भक्त, उन्हें उससे विरत करना होगा।

राष्ट्रीय एकीकरण और मुसलमान

उपासना, मत और ईश्वर संबंधी विश्वास की स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति की परम्परा रही है। भारतीय संविधान ने भी इसे स्वीकार किया है। किन्तु मजहब के आधार पर किसी को 'अल्पमत' अथवा 'बहुमत' वाला मानना न तो राष्ट्रीय एकात्मता के लिए हितावह है और न सत्यसंगत ही। ■

(डॉ. चन्द्रिका प्रसाद शर्मा संपादित पुस्तक 'कुछ लेख, कुछ भाषण' से साभार)

श्रद्धांजलि : 125वीं जन्म जयंती : 14 अप्रैल 2016

डॉ. भीमराव अम्बेडकर : एक दूरद्रष्टा विचारक

गत 14 अप्रैल 2016 को देश डा. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मनाया और लोग उन्हें एक सामाजिक क्रांतिकारी आर दलित चिंतक के रूप में भारतीय संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट के रूप में स्मरण किया। बाबा साहेब अम्बेडकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व मुख्य निर्माता, सामाजिक क्रांतिकारी और दलित चिंतक के रूप में याद किए जाते हैं। दरअसल, बाबा साहेब एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और उन्होंने राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न आयामों में भारी योगदान किया था।

अपने अध्ययन तथा कानून, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स एंड पॉलिटिकल सांइस से विभिन्न प्रकार के डाक्ट्रेट की डिग्री ली, साथ ही उन्होंने एक एकेडेमिशियन और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न विषयों पर निर्भय होकर लिखा भी। उनके लेखों को मोटे तौर पर विभिन्न भागों के विभाजित किया जा सकता है, जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता, एकेडिमिशियन, राष्ट्रवादी, आध्यात्मिक नेता और इसी प्रकार के कई रूपों में उनके लेख हमारे सामने आते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता और जन-नेता के रूप में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने समय से बहुत पहले अनेक मुद्दे उठाए, अत: उनकी क्रांतिकारी पहुंच ऐसे सामाजिक सुधार का एजेण्डा बन गई थी जिससे जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता पर उनका ध्यान विशेष रूप से बना रहा था। एक एकेडिमिशयन के रूप में उन्होंने अपने समय के ज्वलंत मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं।

बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महार परिवार में हुआ, जो उस समय के महू में था, जो अब मध्य प्रदेश में आता है। मूल रूप से उनका परिवार आज के महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में अम्बावाडे शहर में आता है। बचपन में स्कूल जाते हुए उन्हें अनेक प्रकार की भेदभावपूर्ण वाली समस्याएं आई, क्योंकि वह महारों के निम्न जाति में आते थे परन्तु उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने का दृढ़ संकल्प बनाए रखा। एलफिंस्टन कॉलेज से विद्यार्थी के रूप में बड़ौदा के गायकवाड शासक साहयाजी राव III ने अमेरिका में उच्च अध्ययन के लिए पच्चीस रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप मंजूर की थी। वे डाक्ट्रेट में अध्ययन के लिए अमेरिका गए और इकॉनामिक तथा राजनीतिक विज्ञान में डिग्रियां प्राप्त की। वापस लौटने पर वे बड़ौदा सरकार की सेवा में शामिल हुए और उन्होंने जातिगत भेदभाव और उस समय भारतीय समाज में फैले अस्पृश्यता के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लड़ाई शुरू की। उनकी वंचित तथा दलित वर्गों के प्रति लड़ाई ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर का राजनैतिक नेता बना दिया।

बाबा साहब को भारतीय संविधान का प्रमुख निर्माता माना गया है जिन्होंने देश में उदार लोकतंत्र की नींव रखी, जिसमें उम्मीद की गई कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगा। परन्तु उनके व्यक्तित्व का दूसरा आयाम की खोज नहीं की जा सकी है। बाबा साहेब का एकेडेमिशयन ओर चिंतक का स्वरूप, विभाजन के समय जनसंख्या की अदला-बदली की वकालत, भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक रंग बनाए रखने, राजनीतिक रूप में उनका बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय, जो आध्यात्मिक खोज का परिणाम था, इस्लाम, ईसाइयत और मार्क्सवाद को त्यागने का विचार तथा भूतकाल के भारत के बारे में उनके लेख तथा अन्य बहुत सी इसी प्रकार के आयामों ने बाबा साहेब के व्यक्ति का अध्ययन अनुसंधान आदि करना आज भी अपेक्षित है।

राष्ट्रवादी के रूप में बाबा साहेब ने हमेशा ही सबसे आगे राष्ट्रीय हितों को सामने रखा। ■

कृष्णानगर (पश्चिम बंगाल) रैली

तृणमूल कांग्रेस अपना होश खो बैठी है : मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर और शहीद मीनार, कोलकाता में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने पश्चिम बंगाल की दुर्दशा व कुशासन के लिए तृणमूल कांग्रेस, वामदल और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन की मुख्य बातें-

- पराजय की कगार पर खड़ी तृणमूल कांग्रेस अपना होश खो बैठी है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, इसलिए अब वह किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि चुनाव आयोग से लड़ रही है।
- चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, विश्व भर में इसकी प्रतिष्ठा है, हम सभी राजनीतिक दलों का यह दायित्त्व बनता है कि हम इन संस्थाओं का सम्मान करें और निर्धारित नीति एवं नियमों का पालन करें। अगर हम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगें तो यह देश नहीं चल पायेगा।
- इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल नेताओं के चुनाव के बुरे आचरण को लेकर नोटिस जारी किया था, दीदी की जिम्मेवारी बनती थी जवाब देने की लेकिन वह तो यह बयान दे रहीं हैं कि वह इलेक्शन कमीशन को 19 तारीख के बाद देख लेंगीं। अगर दीदी को कुछ देखना ही था तो बीते पांच वर्षो में वह पश्चिम बंगाल के लोगों की गरीबी देखतीं, राज्य की जनता के दु:ख दर्द को देखती, इनकी परेशानियों को समझतीं, पर नहीं, इन्हें तो बस किसी तरह सत्ता पाने से मतलब है।
- दीदी को राज्य की जनता को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी लोकतंत्र में आस्था है कि नहीं, उन्हें भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों में आस्था है कि नहीं।
- सुना है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने दिया है। अगर यह सही है तो यह एक बड़ा संवैधानिक संकट है। सरकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह चुनाव नियमों का खुला उल्लंघन है। सरकार का दुरुपयोग करने के कारण ही इंदिरा गांधी जी की सदस्यता भी छह सालों के लिए निलंबित कर दी गई थी। कानून तो कानून का ही काम करेगा लेकिन पराजय के डर से इस तरह यदि व्यवस्थाओं को ही नष्ट करने की कोशिश की गई तो इतना बड़ा देश नई मुसीबतों में फंस जाएगी।
- एक समय था जब पश्चिम बंगाल पूरे भारत का मार्गदर्शन करता था लेकिन आजादी के बाद पहले कांग्रेस ने, फिर लेफ्ट ने और फिर दीदी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद करके रख दिया, कुछ नहीं बचने दिया।
- केरल में कम्युनिस्ट पार्टियां के लीडर कह रहे हैं कि इस देश में कांग्रेस से बुरा कोई दल नहीं है और वही लोग बंगाल में आकर एक हो जाते हैं। केरल में कुश्ती और बंगाल में दोस्ती, गठबंधन अगर करना है तो केरल में भी होना चाहिए था नहीं तो पश्चिम बंगाल में भी नहीं होना चाहिए था। यह आदर्शों, सिद्धांतों अथवा पश्चिम बंगाल की भलाई के लिए किया गया गठबंधन नहीं है, बल्कि अपना वजूद बचाने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का संघर्ष है।
- जिस धरती पर उत्तम कवियों के विचार हमें सुनने को मिले, जिस धरती से राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे मनीषियों ने विश्व का मार्गदर्शन किया था, दु:ख की बात यह है कि आज वह धरती बम बनाने की फैक्ट्री बन गई है।
- कांग्रेस और तृणमूल दोनों का एक ही गोत्र है, इन दोनों ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद करके रख दिया है।

- पहले शारदा अब नारदा, मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग कैमरे पर सरेआम मनी लेते पाये गए। कैमरे पर सिर्फ पैसों का लेन-देन नहीं हो रहा था, राज्य के गरीब लोगों के भविष्य के साथ सौदा किया जा रहा था, उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा था। ये रुपये जनता-जनार्दन के पैसे हैं जिसे कैमरे पर सरेआम लूटा गया।
- मैं कांग्रेस, लेफ्ट और दीदी से सवाल पूछता हूं कि गरीबों को इन चिट फंडों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया, क्यों गरीबों की भलाई के लिए काम नहीं किये गए? हमने सरकार में आते ही गरीबों की भलाई के लिए देश के करोड़ों गरीब के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से बैंकों के दरवाजे खोल दिए, जिससे कि शारदा चिटफंड जैसी ठग कम्पनियाँ गरीबों का दोहन न कर सके। हमने गरीबों को न्यूनतम प्रीमियम पर जीवन ज्योति बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना उपलब्ध कराई। अगर यह काम पहले हो गया होता तो आज बंगाल में गरीबों के पैसे न लुटते।
- कहने को तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे के खिलाफ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन केंद्र में ये तीनों एक हो जाते हैं। हमने पश्चिम बंगाल के तृणमूल नेताओं के घूसकांड मामले को लोक सभा में तो एथिक्स कमिटी को सौंप दिया, लेकिन राज्य सभा में यह काम कांग्रेस, लेट और तृणमूल की जुगलबंदी के कारण संभव नहीं हो पाया।
- दीदी, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लाठियां खाती थीं, लोगों ने तो आपको पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाने के लिए वोट किया था लेकिन आज इतना बड़ा नारदा हो गया, आपमें ही इतना बड़ा परिवर्तन हो गया।
- अगर पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो राज्य से सिंडिकेट कल्चर का खत्म करना होगा। कोलकाता में जो दर्दनाक ब्रिज हादसा हुआ वह सिंडिकेट कल्चर का ही परिणाम था।
- केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों का भविष्य संवारने के लिए वचनबद्ध है लेकिन यदि यहां की राज्य सरकार ही ऐसा करना नहीं चाहती तो राज्य की जनता का भविष्य कैसे बदल सकता है?
- आज तक दिल्ली में जो सरकारें बैठीं, उन्होंने पूरब की ताकत को ना पहचाना और ना योजना बनाई। हमारा मानना है कि देश के पूर्वी क्षेत्र का विकास किये बिना देश का विकास संभव नहीं हो सकता।
- देश की जनता ने सबके शासन का मॉडल देखा है। पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस के शासन को भी देखा, कम्युनिस्ट पार्टियों के शासन को भी देखा, व्यक्ति केंद्रित क्षेत्रीय शासन व्यवस्था भी देखी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी देखा है। जहां भी भाजपा की सरकारें है वहां हमने प्रगति के नए मापदंड स्थापित किये हैं।
- हमने कृषि के विकास के लिए कई योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया है, हमने 'सुरक्षित फसल, समृद्ध किसान' का नारा देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत की, फसलों के नुकसान पर होने वाले मुआवजे के मापदंडों को बदला, फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की, खेतों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की और हर खेत तक पानी पहुंचाने का प्रबंध किया।
- हमने गरीब युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत तीन करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को सवा लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। हम देश की आम जनता को ताकत देना चाहते हैं। मेरा सपना है - 2022 तक हर गरीब का अपना खुद का घर होना चाहिए।
- मैं अपने तीन सूत्री एजेंडे पर काम करता हूँ - पहला एजेंडा - विकास, दूसरा एजेंडा - तेज गति से विकास और तीसरा एजेंडा - चारों तरफ विकास। हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में ही है। हम देश के हर हिस्से का एक सामान विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम राज्य के छात्रों के लिए पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई और बुजुर्गों के लिए दवाई की राज्य में ही समुचित व्यवस्था करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं।
- हमें भी केंद्र में आये हुए दो साल हो गए, एक पैसे के भी भ्रष्टाचार की खबर आई क्या? विपक्ष एक भी आरोप हम पर नहीं लगा पाया। बस एक बार हमें सेवा का मौका दीजिये, हम पश्चिम बंगाल में एक भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त एवं विकासोन्मुखी सरकार की नींव रखेंगें और पश्चिम बंगाल को देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाएंगें। ■

प्रधानमंत्री द्वारा श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में कटरा का दौरा किया। उन्होंने माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री एन एन वोहरा, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री निर्मल सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्री बाली भगत भी मौजूद थे।

300 करोड़ रुपये में बना 230 बिस्तरों का अस्पताल

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा के पास रियासी जिले में 300 करोड़ रुपये की लागत से 230 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण करवाया है। इस अस्पताल में 15 मार्च से ही लोगों के लिए नि:शुल्क ओपीडी सेवा और नैदानिक परीक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। आठ अप्रैल से ही अस्पताल में पूर्ण रूप से कार्य शुरू हो गया था।

आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये अस्पताल

इस अस्पताल में रोगियों के लिए सर्वोत्तम संभव निदान और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक कम्प्यूटरीकृत उपकरण लगाए गए हैं। अस्पताल में हृदयरोग विज्ञान, कॉर्डियो-थोरासिस सर्जरी, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी इत्यादि समेत 20 से अधिक विभागों में चिकित्सा एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल लीनियर एक्सीलेटर, बैकी थेरेपी, गामा कैमरा, एमआरआई और अन्य नए उपकरणों समेत अत्याधुनिक कम्प्यूटरीकृत नैदानिक एवं उपचार उपकरणों से युक्त है। अस्पताल में उच्च सुविधाओं से युक्त दो क्रिटिकल केयर एंबुलेंस हैं। इसमें अत्याधुनिक डायलसिस इकाई भी है।

पानी संग्रहण और सौर ऊर्जा का उपयोग भी होगा

बारिश के पानी के संग्रहण, सौर ऊर्जा के उपयोग, अपशिष्ट पदार्थों को जलाए जाने की सुविधा, निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए जनरेटर, मल-जल उपचार के दो संयंत्र, शॉपिंग परिसर, पार्किंग की सुविधा और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी इस अस्पताल में हैं। श्राइन बोर्ड ने सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के संचालन के लिए बेंगलुरु स्थित नारायण हृदयालय प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है, जो देशभर में 32 अस्पताल संचालित करता है।

युवा आबादी की सहायता से बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है: मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण भी दिया। प्रधानमंत्री ने छात्रों का आह्वान किया कि वे हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि इस विश्वविद्यालय के लिए धन का एक स्रोत गरीब तीर्थ यात्रियों द्वारा माता वैष्णो देवी श्राइन में किया गया दान रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को गरीबों के लिए कुछ करने की शपथ भी लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अपनी युवा आबादी की सहायता से बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और जब भी ज्ञान का युग रहा है, भारत ने राह दिखाई है। प्रधानमंत्री ने शैक्षिक रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए छात्राओं की सराहना की। उन्होंने दीपा करमाकर की उपलब्धि का भी उल्लेख किया, जो

शेष पृष्ठ 21 पर

भारत की आर्थिक प्रगति पड़ोसियों के विकास के बिना अधूरी : प्रधानमंत्री

दो दिन की भारत यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बीच दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मालदीव भारत के कुछ सबसे पुराने मित्रों में से है और हम एक दूसरे के साथ ऐतिहासिक सांस्कृति मूल्यों को साझा करते हैं। मेरा मानना है कि भारत की आर्थिक प्रगति उसके पड़ोसियों के विकास के बिना अधूरी है। हमारी सोच है कि पड़ोसी पहले।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मालदीव का विकास, इसकी आर्थिक प्रगति और सुरक्षा भी हमारा लक्ष्य है। मैंने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के साथ विभिन्न मुद्दों पर गंभरता से चर्चा की है। हम विभिन्न मुद्दों पर जागरूक और सजग हैं, जिनमें आतंकवाद भी शामिल है। हमने इसे

लेकर जानकारी साझा करने की बात पर भी सहमति जताई है।

मालदीव के राष्ट्रपति की इस भारत यात्रा के संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत और मालदीव्स की सहभागिता के इतिहास में एक अहम दिन है। उन्होंने कहा कि मालदीव्स भारत के सबसे घनिष्ट सहयोगियों में से एक है। संस्कृति की पुरानी कड़ियाँ, दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी मेल-जोल, और हिंद महासागर की लहरें, हमें जोड़ती हैं। मालदीव्स की प्रगति, सुरक्षा और आर्थिक विकास, जितना आपका मकसद है, उतना ही भारत का भी लक्ष्य है। मालदीव्स की स्थिरता और सुरक्षा भारत के सामरिक हितों से सीधे-सीधे जुड़ी हुई है।

श्री मोदी ने कहा कि मालदीव्स की समस्याएं, हमारी भी चिंता हैं। मेरा मानना है कि भारत का आर्थिक विकास हमारे पड़ोसी देशों की तरक्की के बिना अधूरा है। 'पड़ोसी प्रथम' न सिर्फ हमारी नीति है, बल्कि हमारे सिद्धांतों का अहम हिस्सा भी है। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति यामीन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों से जुड़े सभी

विदेश मंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति से की मुलाकात

केन्द्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 11 अप्रैल को मालदीव के राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम से मुलाकात की। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विचार-विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने विदेश मंत्री से मुलाकात की पुष्टि करते हुए ट्वीट कर कहा कि आपसी द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने औपचारिक वार्ता से पहले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम से मुलाकात की। गौरतलब है कि विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा नवंबर 2014 और उसके बाद अक्टूबर 2015 में 15 वर्षों बाद भारत-मालदीव संयुक्त आयोग में शामिल होने के लिए मालदीव गई थीं।

भारत और मालदीव ने कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं दोहरे कराधान को टालने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार और मालदीव गणराज्य ने कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन से अर्जित होने वाली आमदनी पर दोहरे कराधान को टालने के लिए 11 अप्रैल को दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजधानी में मालदीव के राष्ट्रपति के आगमन के दौरान इन दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान पर किया गया समझौता पारदर्शिता एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है। इसके दायरे में वे सारे कर आते हैं, जो भारत एवं मालदीव की सरकारों द्वारा लागू किये गए हैं।

दूसरे समझौते के जरिए भारत और मालदीव के हवाई उद्यमों को दोहरे कराधान से राहत दी गई है। भारत के उद्यमों को अतंर्राष्ट्रीय हवाई यातायात से जुड़े अपने परिचालन से प्राप्त होने वाली आमदनी को मालदीव के कर से छूट देते हुए यह रियायत दी गई है। इसी तरह मालदीव के उद्यमों को अतंर्राष्ट्रीय हवाई यातायात से जुड़े अपने संचालन से प्राप्त होने वाली आमदनी को भारत के कर से छूट देते हुए यह राहत दी गई है। अत: इस समझौते से कर के मामले में भारत और मालदीव के हवाई उद्यमों का संशय समाप्त हो जाएगा।

विषयों पर विस्तार से बातचीत की है। ये साफ है कि भारत और मालदीव्स के संबंधों का दायरा हमारे साझे सामरिक, सुरक्षा, आर्थिक, और विकास के मकसद से परिभाषित है। हम मालदीव्स की सुरक्षा जरूरतों के प्रति जागरुक हैं। राष्ट्रपति यामीन भी इस बात से सहमत हैं कि मालदीव्स भारत के सामरिक और सुरक्षा हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा सांझा मत है कि भारत और मालदीव्स की समंदर की सीमाओं की सुरक्षा का सबसे बेहतर और इकलौता जरिया हमारी मजबूत दोस्ती है। पूरे हिंद महासागर में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों का विकास, लगातार ट्रेनिंग और क्षमता में सुधार, जरूरी उपकरणों की सप्लाई, और समंदर की निगरानी इसके अहम अंग होंगे।

श्री मोदी ने कहा कि हमने मालदीव्स में पुलिस अकादमी की स्थापना, रक्षा मंत्रालय की इमारत का निर्माण और सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी तेजी लाने का फैसला किया है। दक्षिण एशिया में सीमा पार से आतंकवाद और कट्टरवादी सोच के हावी होने से हो रहे नुकसान और खतरों के प्रति राष्ट्रपति यामीन और मैं पूरी तरह सजग हैं...सचेत हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दोनों ने व्यापार, आर्थिक और निवेश में साझेदारी के विकास पर भी विस्तार से बात की। भारत में होने वाले तीसरे मालदीव्स इनवेस्टमेंट फोरम का हम स्वागत करते हैं। ये दोनों देशों के बीच निवेश और कारोबारी रिश्तों को और मजबूत करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सहभागिता हमारी प्राथमिकता है। साल 1995 में भारत ने मालदीव्स में जो अस्पताल बनाया था, उसको उन्नत बनाना, डॉक्टरों की टीम को और मजबूत करना, स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाओं का निर्माण, दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आधुनिक तकनीक, इसके अहम अंग हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आज हमारे सहयोग की उड़ान, जल और थल को पार कर अंतरिक्ष को छू रही है। साउथ एशिया सैटेलाइट के समझौते पर आज हुए हस्ताक्षर से मालदीव्स और दूसरे दक्षिण एशियाई देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भरपूर लाभ मिलेगा। मालदीव्स सांस्कृतिक धरोहर का धनी है। प्राचीन मस्जिदों और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और उनकी मरम्मत के लिए आज हुआ समझौता हमारे सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत बनाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति यामीन जी ने मालदीव्स में हो रहे राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारों के बारे में भी मुझे जानकारी दी है। भारत हर ऐसी कोशिश का समर्थन करता है जो मालदीव्स को, उस के नागरिकों को और राजनीति को सशक्त बनाए। मालदीव्स की सफलता के सफर में भारत एक ऐसा दोस्त है जो हर हालात में मालदीव्स के साथ कदम से कदम मिला कर चलेगा । भारत हमेशा मालदीव्स की जनता का सुदृढ़ मित्र और विश्वसनीय पार्टनर रहेगा। ■

भारत की उच्च विकास दर बरकरार : अरुण जेटली

वाशिंगटन डी.सी. के आईएमएफसी पूर्ण सत्र में केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने 16 अप्रैल को अन्य मुद्दों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। यहां प्रस्तुत है उनके विचारों का संपादित पाठ-

मैं प्रबंध निदेशक के वैश्विक नीति एजेंडे (जीपीए) का स्वागत करता हूँ। हालांकि हम जीपीए का व्यापक रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन मैं व्यापक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और भारतीय अर्थव्यवस्था के विषय में उनके संबंध में कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1. जीपीए में किए गये उल्लेख के अनुसार वैश्विक वृद्धि अभी भी निराशाजनक बनी हुई है। उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के पिछले अनुमानों की तुलना में न्यून दर पर रहने की संभावना है।

2. यहां मुख्य रूप से जारी चिंताएं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों के फैलाव के निहितार्थ हैं। जैसाकि मैंने पिछले अवसरों पर भी बल दिया है कि नीति समायोजन को इस तरह से किया जाना चाहिए कि इसका अन्य देशों पर नकारात्मक प्रभाव कम से कम पड़े। हमारा प्रस्ताव है ऐसी नीतियों के बाहरी प्रभाव की स्वतंत्र निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था

3. भारत अपनी उच्च विकास दर बनाए हुए है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अवसादपूर्ण वैश्विक स्थिति में भी बढ़ती हुई वास्तविक आय और घरेलू मांग के साथ भारत को 'आशा के प्रकाश स्तम्भ' के तौर पर माना जाता है।

4. भारत ने निर्यात में गिरावट और दो लगातार वर्षो में मानसून की कमी के बावजूद, पिछले वर्ष की 7.2 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान पेश किया है। यदि मानसून सामान्य होता है और बाहरी मांग में वृद्धि होती है तो इस वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

5. हम वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।

निवेश संवर्द्धन

प्रक्रियाओं को सरल बनाने और युक्तिसंगत बनाने के द्वारा व्यापारिक परिवेश को बढ़ावा देने और निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रगतिशील कर नियमों को कार्यान्वित करने के लिए कई पहल की गई हैं। कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए काफी हद तक 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्ट अप इंडिया' जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से विनिर्माण और स्टार्ट अप उद्यमशीलों में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है।

व्यापक आर्थिक नीति

हम मध्यम अवधि के राजकोषीय समेकन योजना के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें हमारी राजकोषीय घाटे को 2015-16 के 3.9 प्रतिशत से 2016-17 में 3.5 प्रतिशत पर लाने की योजना है। इसी तरह से चालू खाता भी वर्ष 2015-16 में 1.0-1.5 प्रतिशत की श्रेणी में बनी हुई है। 2015-16 के लिए, मुद्रास्फीत के करीब 5.5 प्रतिशत के आसपास होने की संभावना है और इसमें आगामी 5 प्रतिशत से कम होगी।

कर सुधार

हमने छोटी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कराधार के बोझ को कम कर दिया है। इस तरह का कर युक्तिकरण भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। एक बार लागू होने के बाद, कराधान को राष्ट्रव्यापी तौर पर एकीकृत करता है और लेनदेन की लागता को कम करने वाला वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विकास को एक महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगा।

संरचनात्मक सुधार और नई पहलें

सरकार ने बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बिना बैंक खातों वाले व्यक्तियों के लिए 200 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोल दिये गये हैं। विशिष्ट पहचान 'कौशल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों के लिए एक ऋण वितरण कार्यक्रम के माध्यम से एक मुद्रा बैंक का शुभारंभ किया गया है। फसल नष्ट होने के कारण किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आकर्षक प्रीमियम दरों पर एक नए फसल बीमा कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका

मैं अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका के बारे में चर्चा करूँगा। यह कोष ने केवल एक सार्वभौमिक सुरक्षा तंत्र है बल्कि एक ज्ञान संसाधन भी है। हालांकि, इसे और प्रभावी भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की वृद्धि के साथ और मजबूत किए जाने की जरूरत है। हम मानते हैं कि आईएमएफ द्वारा सभी तीन संभावित घटक–आत्म बीमा, द्वीपक्षीय बीमा/बहुपक्षीय समझौते और बहुपक्षीय समझौते एक मजबूत और निष्पक्ष वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट के वैध और पूरक घटक हैं। हम यह भी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस जिम्मेदारी का निर्वहन सबसे अच्छी प्रकार से कर रहा है।

मैं स्वागत करता हूँ कि लंबे समय से लंबित आईएमएफ सुधार 2010 में आखिरकार प्रभाव में आ गये हैं, लेकिन कोष अंशभागिता अभी भी वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करते। हमें 15वीं अंशभागिता की सामन्य समीक्षा को शीघ्रता से पूर्ण करने और अक्टूबर 2017 तक की समय सीमा के मुताबिक चलने की आवश्यकता है। इस जटिल विश्व के दौर में बहुपक्षीय संस्थानों में एक सुरक्षा तंत्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। ■

पृष्ठ 17 का शेष...

ओलंपिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने कहा कि अभी दीपा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। जरूरी नहीं कि सुख सुविधा हों वही कुछ बनता है, बनने के लिए हौसले की जरुरत होती है। दशरथ मांझी का नाम कौन नहीं जानता है। बिहार का एक किसान रास्ता बना दिया।

अपने भाषण में श्री मोदी ने कहा, किसी को पूछो आगे क्या करना है तो कोई कहता पहले तो पढ़ाई कर लूं। जो इतनी ही सोच रखता है उसके लिए कल के बाद एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। जीवन के हर पल को हम देखते जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या योगदान होगा।

श्री मोदी ने कहा कि जो नहीं बने उसे भूल जाइए, जो बने हैं उसे जिएं। कुंठा, असफलता बोझ नहीं बननी चाहिए। वो आगे बढ़ने का रास्ता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप यहां से कई सपने लेकर जा रहे हैं। कभी कभार बनने के सपने बोझ भी बन जाते हैं जब आप कुछ बनना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री ने बाद में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड खेल परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती की उनके उस ऊर्जावान नेतृत्व और उत्साह के लिए सराहना की, जिसके साथ उन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य के भविष्य की बात की है। खेल परिसर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में खेल भावना का निर्माण करने के लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने फीफा अंडर-17 विश्व कप का भी उल्लेख किया, जिसकी भारत 2017 में मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए खेल का जश्न मनाने का अवसर होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी के विजन-इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस विजन को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास की दिशा में काम करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएंगे।

विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के बाद मोदी ने कटरा में एक जनसभा को भी संबोधित किया। यहां अपने भाषण की शुरुआत करते हुए मोदी ने पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद को याद किया। मोदी ने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है। मुफ्ती साहब की गैरहाजिरी हम महसूस करते हैं। जब भी हमारा मिलना हुआ एक बात उनके दिल में रहती थी कि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो दूरी है उसको मिटा देना है। जब विकास की भावना दिल में रहती है तो विकास होता है। महबूबा जी को बहुत बधाई देता हूं। जम्मू-कश्मीर देश के सभी राज्यों के छात्रों को अपने यहां शिक्षा दे रहा है, जो खेलता है वही खिलता है। ■

वैश्विक समुद्री क्षेत्र में पुनर्जीवित हो भारत की प्रतिष्ठा

✍ नरेंद्र मोदी

हम सभी जानते हैं कि समुद्र पृथ्वी की सतह का सत्तर प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं। हम यह भी जानते है कि पृथ्वी पर मौजूद पानी का सत्तानवे प्रतिशत समुद्रों में पाया जाता है। इसलिये समुद्री परिवहन आवागमन का सर्वाधिक विस्तृत साधन हो सकता है। पर्यावरण के लिहाज से भी यह सबसे अच्छा परिवहन है। हालांकि, इस तथ्य में एक पक्ष और है। वह यह है कि हमारे ग्रह पर रहने योग्य स्थानों का निन्यानवे प्रतिशत समुद्र में है। इसका अर्थ यह है कि हमारी जीवनचर्या, परिवहन के साधन एवं व्यापार का आचार समुद्रों के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि न पहुंचाए। साथ ही समुद्री सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता एवं समुद्री रास्तों की संरक्षा एवं सुरक्षा भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों ने दर्शाया है कि समुद्रों एवं हिमनदों की पारिस्थितिकी में परिवर्तन मानव व्यवहार तक में बदलाव ला सकता है। द्वीप देशों एवं विशेषकर समुद्रवर्ती समाजों में यह पहले ही चिंता का कारण बना हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इस समिट में समुद्र संबंधी आर्थिक मसलों पर चर्चा के दौरान इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। समुद्र में होने वाली डकैती का खात्मा इसका अच्छा उदाहरण है कि समुद्रवर्ती देशों के संयुक्त प्रयासों से किस प्रकार उत्कृष्ट नतीजे पाए जा सकते हैं।

14 अप्रैल 2016 को इस महत्वपूर्ण समिट को आयोजित करने का एक कारण है। आज भारत के एक महान पुत्र जो मुंबई में भी रहे थे एवं कार्य किया था, की 125 वीं जन्मशती है। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात कर रहा हूं जो हमारे संविधान के शिल्पकार हैं। वह भारत में जलक्षेत्र एवं नदियों में होने वाली परिवहन नीति के निर्माता भी हैं। आज के शुभ दिन मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अगाध सम्मान देता हूं। मैं यह अभिलाषा भी रखता हूं एवं प्रार्थना करता हूं कि उनकी शिक्षाएं देश निर्माण हेतु हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहें।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों ने दर्शाया है कि समुद्रों एवं हिमनदों की पारिस्थितिकी में परिवर्तन मानव व्यवहार तक में बदलाव ला सकता है। द्वीप देशों एवं विशेषकर समुद्रवर्ती समाजों में यह पहले ही चिंता का कारण बना हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इस समिट में समुद्र संबंधी आर्थिक मसलों पर चर्चा के दौरान इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। समुद्र में होने वाली डकैती का खात्मा इसका अच्छा उदाहरण है कि समुद्रवर्ती देशों के संयुक्त प्रयासों से किस प्रकार उत्कृष्ट नतीजे पाए जा सकते हैं।

हम में से बहुत लोगों को यह पता नहीं है कि बाबासाहब ने पानी, नौपरिवहन एवं विद्युत संबंधी दो शक्तिशाली संस्थाओं की रचना की है। यह थे: केंद्रीय जलमार्ग, सिंचाई एवं नौपरिवहन आयोग एवं केंद्रीय तकनीकी वैद्युत बोर्ड। इन संस्थाओं का निर्माण करते समय उनके विचार उनकी जबरदस्त दूरदर्शिता का उदाहरण हैं।

3 जनवरी, 1945 को उनके संबोधन से मैं उद्धरण देता हूं:

'इन दो संस्थाओं की रचना हेतु निहित उद्देश्य इस पर सुझाव देना है कि जल संसाधन किस प्रकार बेहतर इस्तेमाल किये जा सकते हैं एवं एक परियोजना का सिंचाई के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु किस तरह उपयोग हो सकता है।'

डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे देश के लाखों निर्धनों की खुशहाली के अध्याय की नींव के तौर पर नयी नौपरिवहन नीति की महत्ता पर जोर दिया था। मैं यह बता कर प्रसन्न हूं कि बाबासाहब की दूरदर्शिता एवं अग्रदृष्टि के अनुरूप हमने राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की है। सात प्रतिशत से अधिक की विकास दर के साथ भारत आज तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक ने आने वाले दिनों में और बेहतर संभावनाएं जताई हैं। हमारी विकास दर को तेज एवं समावेशी बनाना सुनिश्चित करने के लिये हम सक्रिय कदम उठा रहे हैं। यह समिट भारत को आर्थिक तौर पर शक्तिसम्पन्न, सामाजिक

एवं तकनीकी तौर पर समृद्ध बनाने के बाबासाहब के सपनों को सच करने की दिशा में एक और कदम है।

मेरी समझ में लगभग चालीस देशों से 4500 से भी अधिक पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। मैं विशेषकर प्रसन्न हूं कि कोरियाई गणतंत्र इस आयोजन में साझीदार देश है। मैं कोरिया के राष्ट्रपति को एवं यहां उपस्थित वरिष्ठ मंत्री श्री किम यंग-सक को धन्यवाद देता हूं।

हम भारतीय शानदार समुद्री विरासत के उत्तराधिकारी हैं। लगभग 2500 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता के दौर में गुजरात के लोथल में विश्व का प्रथम बंदरगाह बनाया गया था। यह बंदरगाह जहाजों को जगह देने एवं उनकी देखभाल करने की सुविधाओं से युक्त था। इसका निर्माण ज्वारीय प्रवाहों के अध्ययन के बाद किया गया था।

दो हजार वर्ष पहले लोथल के अतिरिक्त कुछ अन्य भारतीय बंदरगाह भी थे जो वैश्विक समुद्री व्यापार के प्रधान चालक थे। इनमें यह शामिल थे:

- बैरिगजा- जो आज गुजरात में भरूच के तौर पर जाना जाता हैय
- मुजीरिस- जो आज केरल में कोचीन के निकट कोडुंगालुर के तौर पर जाना जाता है।
- कोरकाई- जो आज तूतीकोरिन है,
- कावेरीपत्तिनम जो तमिलनाडु के नागपट्टिनम जनपद में स्थित है,
- एवं अरिकमेडु जो पुदुचेरी के अरियाकुप्पम जनपद में स्थित है।

रोम, ग्रीक, मिस्र एवं अरब देशों के साथ भारत के जोशपूर्ण समुद्री व्यापार के कई उद्धरण भारत के प्राचीन साहित्य में एवं ग्रीक और रोमन साहित्य में मिलते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय व्यापारियों ने दक्षिणपूर्वी एवं पूर्वी एशियाई देशों, अफ्रीका, अरब एवं यूरोप के साथ संपर्क बनाया हुआ था।

हमारी शानदार समुद्री विरासत पर कार्य करते हुए हम इस क्षेत्र में नयी ऊंचाइयां छूने के लिये प्रयासरत हैं। हमारी सरकार के शुरुआती दिनों में हमने सागरमाला कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य हमारी लंबी समुद्री सीमा एवं प्राकृतिक समुद्री अनुकूलता का फायदा उठाना था। इसमें पत्तन आधारित विकास को प्रोत्साहित करने, तटवर्ती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना एवं इन क्षेत्रों में ढांचागत व्यवस्था के विकास पर भी जोर दिया गया था। हम विशेषकर हमारे पत्तनों का विकास कर उनको विशेष आर्थिक क्षेत्रों, पत्तन आधारित छोटे शहरों, औद्योगिक पार्कों, भंडारगृहों, साजोसामान पार्कों एवं परिवहन गलियारों के साथ समेकित करना चाहते हैं।

जबसे मेरी सरकार ने कार्यभार संभाला है, अन्य कार्यों के साथ, हमने भविष्य की अवसंरचना पर भी जोर दिया है। इसमें कई क्षेत्रों में आने वाले वक्त में होने वाला ढांचागत निर्माण सम्मिलित है। पोत, जहाज एवं समुद्र संबंधी अवसंरचना इनमें मुख्य है। यह मेरी सरकार की कोशिश है कि वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा पुनर्जीवित हो।

हमारी शानदार समुद्री विरासत पर कार्य करते हुए हम इस क्षेत्र में नयी ऊंचाइयां छूने के लिये प्रयासरत हैं। हमारी सरकार के शुरुआती दिनों में हमने सागरमाला कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य हमारी लंबी समुद्री सीमा एवं प्राकृतिक समुद्री अनुकूलता का फायदा उठाना था। इसमें पत्तन आधारित विकास को प्रोत्साहित करने, तटवर्ती अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना एवं इन क्षेत्रों में ढांचागत व्यवस्था के विकास पर भी जोर दिया गया था। हम विशेषकर हमारे पत्तनों का विकास कर उनको विशेष आर्थिक क्षेत्रों, पत्तन आधारित छोटे शहरों, औद्योगिक पार्कों, भंडारगृहों, साजोसामान पार्कों एवं परिवहन गलियारों के साथ समेकित करना चाहते हैं।

यहां यह बताना दीगर होगा कि 7500 किलोमीटर लंबी हमारी विशाल समुद्री सीमा बहुत बड़े निवेश की संभावनाओं से भरी है। समुद्री सीमा की लम्बाई के अलावा समुद्र में भारत की संभावनाएं सभी समुद्री राजमार्गों पर इसकी रणनीतिक स्थिति पर टिकी है। इसके अतिरिक्त हमारे पास विशाल एवं उत्पादक भीतरी प्रदेश है जिससे होकर बड़ी नदियों की मंडली बहती है। हमारा समुद्री एजेण्डा भीतरी क्षेत्रों में समानांतर रूप से जारी महत्वाकांक्षी ढांचागत योजनाओं का पूरक होगा।

मैं विश्व के व्यवसायी समाज से आग्रह करता हूं कि हमारे पत्तन आधारित विकास की प्रक्रिया को आकार देने में हमारे साथ साझीदार बनें। मैं आश्वस्त हूं कि भारत की लंबी तटरेखा के साथ-साथ विविध तटवर्ती क्षेत्र एवं तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाला श्रमवान समाज भारत के विकास का आधार बन सकता है।

पत्तनों एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास को संभव कर दिखाने के लिये हमने कई नये कदम उठाए हैं एवं सुधार किये

हैं :

- हमारी मेक इन इण्डिया एप्रोच के तहत हमने भारत को एक विश्वस्तरीय निर्माण केंद्र बनाने के लिये कई कदम उठाए हैं।
- हाल ही में मूडी ने मेक इन इण्डिया पहल की प्रशंसा की है।
- हमने व्यापार को सुगम बनाने के मोर्चे पर कई सुधार किये हैं- हमने इस मामले में विश्व रैंकिंग में 12 अंकों का सुधार किया है।
- सीमा पार होने वाले व्यापार की प्रक्रियाओं में काफी सरलीकरण हुआ है।
- हमने लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को उदार बनाया है, जिसमें रक्षा क्षेत्र एवं जहाज निर्माण भी शामिल हैं।
- शिपिंग पर सेवा कर में मिलने वाली छूट 70 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।
- जहाज के निर्माण में हमने कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान की है।
- जहाजों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय योजनाएं स्वी.त की गई हैं।
- बंकर ईंधन हेतु भारतीय झंडा लगे कंटेनर जहाजों के लिये कस्टम एवं एक्साइज ड्यूटी में छूट दी जाती है।
- समुद्र में लगने वाले करों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया गया है।
- पत्तनों पर अंतिम दूरी तय करने के लिये इण्डियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन नाम से एक नयी कम्पनी स्थापित की गई है।
- हमने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिये एक कानून बनाया है।
- हमने कौशल विकास गतिविधियों को सक्रियतापूर्वक उठाया है।
- हमारे शुरुआती प्रयासों के नतीजे स्पष्त: सामने है:
- इस सरकार के आने के बाद एफडीआई में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वस्तुत: वर्ष2015-16 में अब तक का सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश हुआ है।
- भारत के बड़े पत्तनों द्वारा कार्गो संभालने की सर्वकालिक बड़ी मात्रा वर्ष 2015 में थी।
- पत्तनों की गुणवत्ता के मापदंडों में बहुत अच्छा सुधार हुआ है।
- पत्तनों में भारत का सबसे तेज औसत टर्नअराउंड समय 2015 में था।
- पिछले दो वर्षों में हमारे बड़े पत्तनों ने 165 मिलियन टन क्षमता हासिल की है जिसमें इस वर्ष रिकश्वर्ड बढ़ोतरी हुई है।
- अकेले वर्ष 2015-16 में इन पत्तनों द्वारा 94 मिलियन टन क्षमता जोड़ी गई जो अब तक सर्वाधिक है।
- वैश्विक मंदी के बावजूद पिछले दो सालों में बड़े बंदरगाहों पर ट्रेफिक में चार प्रतिशत से अधिक का विकास हुआ है।
- बड़े बंदरगाहों का पिछले दो सालों में प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा है।
- ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन, जो घट रहे थे, बढ़े हैं।
- अकेले वर्ष 2015-16 में 12 बड़े बंदरगाहों का ऑपरेटिंग प्रोफिट करीब 6.7 बिलियन रुपये बढ़ा है।
- वर्ष 2015-16 के दौरान गुजरात के कांडला बंदरगाह ने 100 मिलियन ट्रेफिक के पड़ाव को पार किया और क्षमता में 20 प्रतिशत की बेहतरी की।
- जवाहरलाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट ने दस बिलियन रुपये का नेट प्रोफिट दर्ज किया साथ ही कार्यक्षमता में बारह प्रतिशत की बढ़ोतरी भी।
- बीते वर्षों के मुकाबले हमारी लैगशिप कम्पनियों जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन एवं कोचीन शिपयार्ड ने अधिक मुनाफा कमाया।

हालांकि यह सिर्फ शुरुआत है। हम और अधिक करना चाहते हैं। हम क्रियान्वयन एवं अमलीजामे की हमारी अपनी क्षमताओं में इजाफा कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना की राष्ट्रीय योजना आज जारी हो गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान बड़े बंदरगाहों ने 250 बिलियन रुपये से अधिक की 56 नई परियोजनाएं शुरू की हैं। इससे वार्षिक तौर पर 317 मिलियन टन की अतिरिक्त पत्तन क्षमता जनित होगी। हमारे दृष्टिकोण में 2025 तक पत्तनों की क्षमता 1400 मिलियन टन से बढ़ाकर 3000 मिलियन टन करने की है। इस विकास को संभव करने के लिये हम चाहते हैं कि पत्तन क्षेत्र में एक लाख करोड़ का निवेश हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुपात में बढ़ते एक्जघ्मि ट्रेड की आवश्यकताओं को देखते हुए पांच नये पत्तनों की योजना है। भारत के बहुत से समुद्रवर्ती राज्य नये बंदरगाहों का विकास कर रहे हैं।

तटीय जहाजरानी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए बहुपक्षीय कदम तथा घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि की आशा से 2025 तक कोयले की तटीय आवाजाही बढ़ेगी। हम निकटतम और क्षेत्रीय पड़ोसियों के साथ शिपिंग तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में काम कर रहे हैं। भारत ने हाल

में बंग्लादेश के साथ तटीय शिपिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते से दोनों देशों को लाभ होगा। भारत ईरान में चाहबहर बंदरगाह विकसित करने के काम में लगा है। विदेशों में समुद्री परियोजनाओं को देखने के लिए इंडिया पोट्स ग्लोबल लिमिटेड के नाम से स्पेशल परपस वेकिल स्थापित किया गया है।

मुझे बताया गया है कि शिपिंग मंत्रालय समुद्री क्षेत्र में निवेश अवसर वाली 250 परियोजनाएं की प्रदर्शनी लगा रहा है। इन परियोजनाओं में 12 बड़े बंदरगाह परियोजनाएं, 08 समुद्री राज्यों में परियोजनाएं और एजेंसियां शामिल हैं। इनमें 100 से अधिक परियोजनाओं की पहचान सागर माला कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है। देश में 14,000 किलोमीटर समुद्री मार्ग है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। मेरी सरकार अवसंरचना एकीकरण के लिए संकल्पबद्ध है। हम निवेशकों के लिए सहज और सहायक वातावरण बनाने और खुले मन से निवेश में सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।

मित्रों, यह सब कुछ सामान्य लोगों के लाभ के लिए किया जा रहा है। यह युवाओं को रोजगार देने के लिए किया जा रहा है और विशेषकर तटीय समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत की आबादी का लगभग 18 प्रतिशत 72 तटीय जिलों में रहती है और यह समुदाय भारत के भू-क्षेत्र के 12 प्रतिशत हिस्से में बसा है। इसलिए तटीय क्षेत्रों तथा तटीय समुदायों का समग्र विकास आवश्यक है। तटीय समुदाय विशेषकर मुछआरा समुदाय के विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सागरमाला कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हम व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे जिसका बल क्षमता सृजन तथा प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी उन्नयन तथा भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में सुधार पर होगा। यह काम तटीय राज्यों के साथ मिलकर किया जाएगा।

इन कार्यक्रमों से अगले 10 वर्षों में लगभग 10 मिलियन रोजगार सृजन होगा। इसमें 04 मिलियन प्रत्यक्ष तथा 06 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार होंगे। आजीविका के अवसरों को और व्यापक बनाने के लिए हम मछली मारने के लिए आधुनिक जहाज विकसित करने की योजना बना रहे हैं। इससे मछुवारा समुदाय को भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम मछली पालन, जल संस्कृति तथा शीत भंडार चेन विकसित करने पर भी बल दे रहे हैं। भारत के बंदरगाह क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक बंदरगाह हैं और दोनों समुद्री क्षेत्र के विकास में योगदान कर रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास का पीपीपी मश्वडल काफी सफल रहा है और इससे आधुनिक टेक्नोलश्वजी और श्रेष्ठ व्यवहारों को अपनाने में मदद मिली है। निजी क्षेत्र के बंदरगाह काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी क्षमता पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हो गई है। कुल कार्गो का 45 प्रतिशत काम वही करते हैं। अधिकतर बंदरगाह नए हैं और उनमें आधुनिक सुविधाएं हैं। ये बंदरगाह कार्य प्रदर्शन और अवसंरचना के मामले में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के स्तर के हैं।

भारत का समुद्री इतिहास गौरवशाली रहा है। हम और बेहतर समुद्री भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। समुद्री क्षेत्र से न केवल आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं बल्कि इससे देश और सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। यह ग्रह तथा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी देश अलग रहकर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रों को इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक दूसरे से सहयोग करना होगा और इस क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना होगा।

भारत का समुद्री इतिहास गौरवशाली रहा है। हम और बेहतर समुद्री भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। समुद्री क्षेत्र से न केवल आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं बल्कि इससे देश और सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। यह ग्रह तथा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी देश अलग रहकर वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रों को इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक दूसरे से सहयोग करना होगा और इस क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य ऐसे सहयोग के लिए मंच प्रदान करना है।

और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि:

- यह भारत आने का सही समय है।
- समुद्री मार्ग से आना और बेहतर है।
- भारतीय जहाज लंबी दौड़ के लिए सुसज्जित हैं।
- मत खोईए यह अवसर।
- इसे खोने का अर्थ है शानदार यात्रा और बड़े गंतव्य को खोना। ■

(मेरीटाइम इण्डिया समिट में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उद्घाटन भाषण पर आधारित)

सुकन्या समृद्धि खाता
बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य की प्रतिबद्धता

✍ आमिर अमीन नौशहरी

लड़कों को प्राथमिकता देने वाली रुढ़िवादी और गलत मानसिकता के कारण कुछ लोग कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। इसके कारण देश में लैंगिक अनुपात में असमानता पैदा होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात 914 दर्ज किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद न्यूनतम है।

संयुक्त राष्ट्र ने इसी वर्ष जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसमें इस स्थिति को 'आपातकालीन' के रूप में उल्लेखित किया गया है। रिपोर्ट में इसका कारण देश में अवैध रूप से किए जाने वाले गर्भपात को बताया गया था।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि देश के समाजिक ढांचे में पुरुषों के बर्चस्व को रोकने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए। इसके लिए स्कूली और उच्च शिक्षा को महत्पूर्ण घटक के रूप में पेश किया गया था ताकि लोग लिंग अनुपात के प्रति जागरुक हो सकें।

जनवरी 2015 में केंद्र सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है ताकि लड़कियों के साथ भेद-भाव समाप्त हो सके। इस योजना के जरिये सरकार देश के लोगों को जागरुक कर रही है ताकि लड़कियों और महिलाओं की स्थिति सुधर सके और लैंगिक समानता का लक्ष्य पूरा हो सके।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के साथ ही 'सुकन्या समृद्धि खाता' योजना भी शुरू की है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के बारे में तो बहुत कुछ लिखा-पढ़ा गया है, लेकिन सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में लोगों को कम जानकारी है।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के साथ ही 'सुकन्या समृद्धि खाता' योजना भी शुरू की है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के बारे में तो बहुत कुछ लिखा-पढ़ा गया है, लेकिन सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में लोगों को कम जानकारी है। उल्लेखनीय है कि सुकन्या समृद्धि खाता छोटी बचत योजना है, लेकिन उसमें देश की लड़कियों के जीवन को प्रभावित करके उनमें आत्म सम्मान की भावना पैदा करने की क्षमता है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित करने और उनका विवाह खर्च मुहैया कराकर उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है।

उल्लेखनीय है कि सुकन्या समृद्धि खाता छोटी बचत योजना है, लेकिन उसमें देश की लड़कियों के जीवन को प्रभावित करके उनमें आत्म सम्मान की भावना पैदा करने की क्षमता है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित करने और उनका विवाह खर्च मुहैया कराकर उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है।

योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक लड़की के नाम से खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन लड़की के 10 वर्ष की आयु होने तक कर सकते हैं। योजना के संबंध में सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह खाता किसी भी डाकखाने और निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है।

जो बैंक योजना के तहत खाता खोलने के लिए अधिकृत हैं उनमें भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैक ऑफ पटियाला, विजया बैक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन ओवसीज बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, देना बैंक, कारपोरेशन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आंध्रा बैंक और इलाहाबाद बैंक शामिल हैं।

योजना के तहत जमा की जाने वाली रकम पर वार्षिक 9.2 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। यह बहुत आकर्षक ब्याज दर है। बहरहाल, सरकार हर वर्ष ब्याज दर की समीक्षा करेगी और आम बजट के समय उसकी घोषणा की

जाएगी। हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम की न्यूनतम सीमा 1000 रुपये और अधिकतम सीमा एक लाख 50 हजार रुपये है। एक महीने में या एक वित्त वर्ष के दौरान रकम जमा करने की बारम्बारता की कोई सीमा नहीं है।

खाते की वैधानिकता उसके खोले जाने की तारीख से लेकर 21 वर्ष की है, जिसके बाद रकम परिपक्व होकर उस लड़की को दे दी जाएगी जिसके नाम पर खाता है। यदि परिपक्वता के बाद खाता बंद नहीं किया जाता है तो बैलेंस रकम पर ब्याज मिलता रहेगा, जिसके बारे में समय-समय पर सूचना प्रदान की जाती रहेगी। यदि लड़की का विवाह 21 वर्ष पूरा होने के पहले हो जाता है तो खाता अपने-आप बंद हो जाएगा।

खाता खोलने की तारीख से 14 वर्ष तक रकम जमा की जाएगी। इसके बाद जमाशुदा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।

यदि न्यूनतम आवश्यक निर्धारित राशि एक हजार रुपये को माता-पिता या अभिभावक जमा नहीं करते हैं तो खाता सक्रिय नहीं माना जाएगा। इस स्थिति में खाते को प्रति वर्ष 50 रुपये पेनाल्टी के सथ दोबारा चालू किया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम रकम भी जमा करनी होगी।

21 वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी होने के पहले खाताधारी लड़की रकम निकाल सकती है बशर्ते कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो। इस स्थिति में वह कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत ही निकाल पाएगी। इसके लिए यह जरूरी है कि निकाली जाने वाली रकम या तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो या विवाह के लिए हो। यह भी उल्लेखनीय है की रकम निकालने के समय खाते में कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक की जमा मौजूद हो।

माता-पिता या अभिभावक लड़की के नाम एक ही खाता खोल सकते हैं और दो लड़कियों के नाम अधिकतम दो खाते खोले जा सकते हैं। यदि पहले एक लड़की हो और उसके बाद जुड़वा लड़कियां पैदा हों या पहली बार में ही तीन लड़कियां पैदा हों तो ऐसी स्थिति में तीन लड़कियों के नाम से बैंक खाते खोले जा सकते हैं।

21 वर्ष की परिपक्वता अवधि पूरी होने के पहले खाताधारी लड़की रकम निकाल सकती है बशर्ते कि उसकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो। इस स्थिति में वह कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत ही निकाल पाएगी। इसके लिए यह जरूरी है कि निकाली जाने वाली रकम या तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो या विवाह के लिए हो। यह भी उल्लेखनीय है की रकम निकालने के समय खाते में कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक की जमा मौजूद हो।

सुकन्या समृद्धि खाता कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें कर छूट प्रदान की जाती है। जमा की जाने वाली रकम और परिपक्व रकम को आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत पूरे कर छूट प्राप्त है।

परिपक्व होने के पहले खाता बंद करने की दूसरी शर्त यह है कि जब सक्षम अधिकारी यह सुनिश्चित हो जाएगा कि अब जमाकर्ता के लिए खाते में रकम जमा करना संभव नहीं है और रकम जमा करने में मुश्किल हो रही है तो खाता बंद किया जा सकता है। खाता बंद करने की और कोई तीसरी वजह नहीं मानी जाएगी।

खाता खोलने की प्रक्रिया बहुत आसान है और इसके लिए तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

1. अस्पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
2. लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के निवास का प्रमाण पत्र, जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन बिल, मतादाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें निवास का उल्लेख हो,
3. पैन कार्ड या हाईस्कूल प्रमाण पत्र भी खाता खोलने के लिए मान्य है। खाता खोले जाने के बाद उसे भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

योजना में अभिभावक उसी समय शामिल हो सकता है जब लड़की के माता-पिता दोनों मृत हो चुके हो या वे खाता खोलने और उसे चलाने के अयोग्य हों। यह उल्लेख जरूरी है जिस लड़की के नाम से खाता खोला जाएगा वह यदि चाहे तो 10 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद खुद अपना खाता चला सकती है।

सुकन्या समृद्धि खाता एक छोटी निवेश योजना भले हो लेकिन यह इस समय बहुत आवश्यक है और इससे लड़कियों को वित्तीय सुरक्षा मिलने में सहायता होगी। ■

(लेखक पीआईबी श्रीनगर में सूचना सहायक हैं)

महामंत्री प्रतिवेदन

एक भारत, श्रेष्ठ भारत की ओर...

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल ने महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 23 जनवरी 2013 से 24 जनवरी 2016 के बीच संपन्न संगठनात्मक कार्यक्रम एवं चुनाव परिणाम से संबंधित विवरण शामिल हैं। इस अवधि में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में जहां पार्टी के 11 करोड़ सदस्य बने और यह संगठनात्मक रूप से अत्यंत सशक्त हुई वहीं श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। हम यहां महामंत्री प्रतिवेदन का पूरा पाठ क्रमशः प्रकाशित कर रहे हैं। प्रस्तुत है तीसरा भाग:

प्रवास

- पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सीधा संपर्क करने हेतु श्री अमित शाह ने विभिन्न प्रदेशों में प्रवास को प्राथमिकता देते हुए जनवरी 2016 तक के अपने 20 माह के कार्यकाल में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रतिदिन 484 किमी के औसत से कुल 2,86,936 किमी की यात्रा की।
- चुनाव के अतिरिक्त किसी और प्रयोजन के लिए पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा निजी विमान के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का निर्णय किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं भी इस नियम का पालन किया।
- सामान्य परिस्थितियों में प्रवास के दौरान महंगे होटलों में ठहरने पर रोक लगा कर सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों को प्रोत्साहित किया गया।
- कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पदाधिकारियों को रात्रि प्रवास के लिए प्रोत्साहित किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं रात्रि प्रवास के आग्रह का पालन किया और 80 प्रतिशत से अधिक प्रवासों में रात्रि निवास किया।
- दमन द्वीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप व अंडमान छोड़कर देश के समस्त राज्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रवास किया और सभी सांसदों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों से संवाद किया। इसी क्रम में अधिकतर स्थानों में शुद्ध रूप से संगठनात्मक विषय चर्चा का केंद्र रहे।
- संगठन में विकेन्द्रीकरण को बल देते हुए क्षेत्रीय बैठकों की परंपरा पुनर्स्थापित की गई।
- राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री व अन्य प्रमुख पदाधिकारियों का हर प्रांत में समय लगाकर विस्तृत प्रवास की योजना बनी है।
- संगठनात्मक एवं चुनावी सफलता की दृष्टि से सात कमजोर राज्यों की विशेष चिंता राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री करेंगे। हर प्रांत के लिए एक केंद्रीय मंत्री को दायित्व मिलेगा।
- अपना संसदीय क्षेत्र छोड़कर अन्य दो संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों ने 36 घंटों का प्रवास किया है।
- सभी सांसदों ने अपने क्षेत्र के सभी विधानसभाओं में प्रवास किया है।

सम्पर्क

- **जन संवाद :** माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आम जन से मिलने हेतु पूरे दिन उपस्थित रहते हैं। कोई भी

पदाधिकारी एवं साधारण कार्यकर्ता भी बिना पूर्व सूचना के मिल सकता है। यह क्रम गत 6 अप्रैल 2015 से निरंतर चल रहा है।

- संगठनात्मक विषयों पर विशेष बल देने के लिए हर तीन महीने में संगठन मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठकें की।
- संगठन और सरकार के बीच समन्वय रखने हेतु प्रधानमंत्री जी और 6 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ श्री अमित शाह ने लगभग एक दर्जन बैठकें की।
- विभिन्न समविचारी संगठनों के साथ निरंतर संपर्क रख पार्टी के साथ समन्वय पर जोर दिया।
- विभिन्न राज्यों के प्रवास के दौरान वह सभी लोग जो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए प्रयासरत थे, उनसे मिलने के लिए हर प्रवास में 2 घंटे का समय अलग से रखा।

चुनावों में प्रदर्शन

लोकसभा चुनाव में जीत के बाद हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम

- इस दौरान हुए 6 राज्यों के चुनावों में भाजपा को अच्छी सफलता मिली जहां पार्टी 4 राज्यों में जीत कर सरकार में आई, वहीं 2 राज्यों में पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला।
- महाराष्ट्र में लम्बे समय से चले आ रहे गठबंधन के टूटने पर अकेले चुनाव लड़कर भाजपा को सबसे अधिक विधायकों वाली पार्टी बनाकर पहली बार प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बनाया ।
- हरियाणा में बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का साहसी निर्णय लिया और पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना।
- लम्बे समय से अस्थिरता से अभिशप्त झारखण्ड में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश को भाजपा के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार दी।
- आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर में भाजपा को सर्वाधिक मत प्रतिशत मिला और गठबंधन सरकार में पार्टी का उपमुख्यमंत्री बना।
- दिल्ली में चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली परन्तु मत प्रतिशत यथावत रहा।
- बिहार में जदयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद पार्टी ने पहली बार 160 सीटों पर चुनाव लड़ा। अनेक प्रयासों के बावजूद प्रदेश की नई परिस्थितियों और विपक्ष के एकीकरण की वजह से पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत में बदलाव

राज्य	पिछले चुनाव में भाजपा का मत प्रतिशत	वर्तमान चुनाव में भाजपा का मत प्रतिशत	मत प्रतिशत में बदलाव	टिपण्णी
महाराष्ट्र	12.2	27.8	+15.6	भाजपा का मुख्यमंत्री
हरियाणा	9.0	33.2	+24.2	भाजपा का मुख्यमंत्री
झारखण्ड	20.2	31.3	+11.1	भाजपा का मुख्यमंत्री
जम्मू एवं कश्मीर	12.5	23.0	+10.5	भाजपा का उप-मुख्यमंत्री
दिल्ली	33.0	32.2	-0.8	भाजपा की पराजय
बिहार	16.5	24.4	+7.9	भाजपा की पराजय

चुनाव परिणाम

लोकसभा सांसद : 281 (एनडीए 336) / 543

राज्यसभा सांसद : 48 (एनडीए 63) / 250

विधायक : 31 प्रांतों में विधानसभा है। इनमें से 25 प्रांतों में 1025 विधायक हैं।

लोकसभा सदस्यों व विधानसभा सदस्यों की दृष्टि से भाजपा पहले स्थान पर है।

विधान परिषद सदस्य : 7 प्रांतों में विधानपरिषद है। इनमें पार्टी के 79 सदस्य हैं।

चुनाव : इसी मध्य कई प्रांतों में स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव सम्पन्न हुए। अनेकों स्थानों पर बहुत अच्छी सफलता मिली, जैसे- असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल आदि। झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, पंजाब व गुजरात पंचायत चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आये। विधानसभा उपचुनाव व विधान परिषद के चुनावों में भी अच्छी सफलता मिली है।

लेह-लद्दाख, चण्डीगढ़, दमन द्वीव, दादरा नगर हवेली व अंडमान निकोबार में नगर पालिका अध्यक्ष/मेयर बने। इसमें से कई स्थानों पर पहली बार इतनी सफलता मिली। मणिपुर विधानसभा के दो उप-चुनाव जीतकर खाता खोला तथा वहां पंचायत चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में संगठनात्मक तैयारी पूरी हुई है। सभी जगह वोट प्रतिशत व सीट बढ़ने की सम्भावना है। अरूणाचल प्रदेश में भाजपा के समर्थन से सरकार बनी है।

प्रशिक्षण अभियान

- संगठन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए अथक प्रयास किये गए और पारम्परिक रूप से चलाये जाने वाले प्रशिक्षण अभियान को नए आयाम दिए। राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर पर पार्टी की स्थापना के बाद पहली बार प्रशिक्षण का आयोजन किया।
- मंडल स्तरीय कार्यकर्ता/ पदाधिकारी प्रशिक्षण अभियान में नए कीर्तिमान बने। इस वर्ष के अभियान में अब तक की सहभागिता 7,76,067 तक पहुंच चुकी है और अभियान अभी भी जारी है। अभी कई प्रांतों में होना शेष है।
- प्रशिक्षण में सरलता के लिए पार्टी के साहित्य को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवा कर वितरित किया।

पार्टी के विभिन्न विभागों की कार्ययोजना का पुनर्गठन

विभिन्न स्तरों पर पार्टी कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं प्रकल्पों का पुनर्गठन करके उनके कार्यक्रमों का विस्तार किया। इस क्रम में पार्टी के विभिन्न विभागों को 19 विभागों में पुनर्गठित किया और 10 नए प्रकल्प बनाये:

केंद्रीय विभाग

1. सुशासन तथा केंद्र -राज्य शासकीय कार्यक्रम समन्वय विभाग
2. नीति विषयक शोध विभाग
3. मीडिया विभाग
4. मीडिया संपर्क विभाग
5. प्रशिक्षण विभाग
6. राजनैतिक प्रतिपुष्टि और प्रतिक्रिया विभाग
7. राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं बैठकें विभाग
8. डॉक्यूमेंटेशन एवं ग्रंथालय विभाग
9. सहयोग, आपदीय राहत व सेवाएं विभाग
10. अध्यक्षीय कार्यालय, प्रवास एवं कार्यक्रम विभाग
11. प्रचार - साहित्य निर्माण विभाग
12. ट्रस्ट समन्वय विभाग
13. चुनाव प्रबंधन विभाग
14. चुनाव आयोग संपर्क विभाग
15. कानूनी और विधिक विषय विभाग
16. पार्टी पत्रिकाएं तथा प्रकाशन विभाग
17. आईटी, वेबसाईट और सोशल मीडिया प्रबंधन विभाग
18. विदेश संपर्क विभाग
19. आजीवन सहयोग निधि विभाग

केंद्रीय प्रकल्प

1. जिला कार्यालय निर्माण प्रकल्प
2. कार्यालय आधुनिकीकरण प्रकल्प
3. ग्रंथालय निर्माण प्रकल्प
4. ई ग्रंथालय प्रकल्प
5. स्वच्छता अभियान प्रकल्प
6. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ प्रकल्प
7. नमामि गंगे प्रकल्प
8. राष्ट्रीय सदस्यता अभियान (प्रकल्प)
9. राष्ट्रीय महा संपर्क अभियान (प्रकल्प)
10. राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान (प्रकल्प)

क्रमश:...